

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17133/2018

अर्जुन सिंह सिसौदिया पुत्र श्री भवन सिंह सिसौदिया, उम्र लगभग 57 वर्ष, गांव व पोस्ट टामटिया राठौड़, तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

----प्रतिवादी

साथ जुड़े

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17465/2018

नारायणलाल उपाध्याय पुत्र श्री नाथूराम उपाध्याय, उम्र लगभग 58 वर्ष, ग्राम व पोस्ट ठिकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री पी.आर. मेहता के साथ
सुश्री तान्या मेहता।

प्रतिवादी के लिए: श्री हेमन्त चौधरी, जी.सी.

श्री विशाल जांगिड़, उप.जी.सी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

19/01/2024

1. मौजूदा संक्षिप्त विवाद इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या याचिकाकर्ता, जिनकी सेवाओं को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3158/1992 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 07.10.1993 के निर्णय और आदेश के अनुसार नियमित किया गया था, उपर्युक्त निर्णय की शर्तों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी पद के नियमित वेतनमान के अनुरूप वेतन और बकाया वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं।

2. नियमितीकरण का आदेश 23.11.1994 को जारी किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति तक लगातार अपने नियोक्ता के साथ अपना मामला आगे बढ़ाया, हालांकि सफलता नहीं मिली। उन्होंने पूरे समय आशावाद बनाए रखा, यह विश्वास करते हुए कि उनकी चल रही कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अंततः उन्हें न्यायालय के फैसले से लाभ होगा, वही कहा। इस प्रक्रिया में, ऐसा लगता है कि उन्होंने आगे के संघर्ष से बचने के लिए अपने नियोक्ता के खिलाफ अवमानना के उपाय अपनाने से परहेज किया, इस प्रक्रिया में अनजाने में सीमाओं के क़ानून को समाप्त होने दिया गया।

3. जब उन्होंने अपने नियोक्ता से राहत पाने की उम्मीद खो दी, तब अंततः उन्होंने 2018 में इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनका मामला एसबीसीडब्ल्यूपी क्रमांक 3158/1992 के उपरोक्त निर्णय के अनुसार राहत पाने का हकदार बनाने वाला निरंतर कार्रवाई का कारण बनता है।

4. उक्त निर्णय की प्रासंगिकता, उचित होने के कारण, त्वरित संदर्भ के लिए यहां नीचे दी गई है:

“याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को जेठमल और अन्य के मामले में दिए गए फैसले के संदर्भ में अनुमति दी जाती है और यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य, जिनके नाम रिट याचिका के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, क्योंकि वे समान

कर्तव्यों, कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा सेवामुक्त किया जा रहा है, वे वर्तमान रिट याचिका दायर करने की तिथि से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के नियमित वेतनमान में वेतन पाने के हकदार हैं।" (जोर दिया गया)

5. उपरोक्त को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में चतुर्थ श्रेणी पद पर वेतन निर्धारण के हकदार थे, जिस पर उनकी सेवाएं रिट याचिका दायर करने की तारीख से नियमित की गई थीं, जिसे उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई थी।

6. जहां तक इस अदालत से संपर्क करने में देरी का संबंध है, भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम तरसेम सिंह: (2008) 8 एससीसी 648 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। उसका प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया गया है: -

“संक्षेप में, आम तौर पर, विलंबित सेवा संबंधी दावे को देरी और खामियों (जहां रिट याचिका दायर करके उपाय मांगा जाता है) या सीमा (जहां प्रशासनिक न्यायाधिकरण में एक आवेदन द्वारा उपाय मांगा जाता है) के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। उक्त नियम के अपवादों में से एक निरंतर ग़लती से संबंधित मामले हैं। जहां सेवा संबंधी दावा किसी निरंतर ग़लती पर आधारित हो, तो राहत तब भी दी जा सकती है, जब सुधार की मांग करने में लंबी देरी हो, उस तारीख के संदर्भ में, जिस तारीख को ग़लती शुरू हुई थी, यदि ऐसी लगातार ग़लती से चोट का निरंतर स्रोत बनता है। लेकिन अपवाद का एक अपवाद भी है। यदि शिकायत किसी आदेश या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में है जो कई अन्य लोगों से संबंधित है या प्रभावित है, और यदि मुद्दे को फिर से खोलने से तीसरे पक्ष के तय अधिकारों पर असर पड़ेगा, तो दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मामला भुगतान या वेतन या पेंशन के पुनर्निर्धारण से संबंधित है, तो देरी के बावजूद राहत दी जा सकती है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यदि दावे में वरिष्ठता या पदोन्नति आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो देरी से दावा पुराना हो जाएगा और विलंब/सीमा का सिद्धांत लागू किया जाएगा। जहां तक पिछली अवधि के लिए बकाया की वसूली की परिणामी राहत का सवाल है, आवर्ती/लगातार गलतियों से संबंधित

सिद्धांत लागू होंगे। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय बकाया से संबंधित परिणामी राहत को आम तौर पर रिट याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले की अवधि तक सीमित कर देंगे।

इस मामले में, सोलह साल की देरी बकाया के लिए परिणामी दावे को प्रभावित करेगी। उच्च न्यायालय द्वारा सोलह वर्षों से संबंधित बकाया भुगतान का निर्देश देना उचित नहीं था, वह भी ब्याज सहित। इसे बकाया से संबंधित राहत को रिट याचिका की तारीख से केवल तीन साल पहले या मांग की तारीख से रिट याचिका की तारीख तक, जो भी कम हो, तक सीमित रखना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में बकाया पर ब्याज नहीं देना चाहिए था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। डिवीजन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें विकलांगता पेंशन का भुगतान देय तिथि से करने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश बहाल किया जाता है।"

7. रिट याचिका दायर करने की तारीख 22.06.1992 होने पर कोई विवाद नहीं है। इसके बावजूद, उनकी सेवाएं 23.11.1994 से नियमित कर दी गईं, जिसका उत्तरदाताओं ने खंडन नहीं किया है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का दावा प्रकृति में आवर्ती है और इसलिए, कार्रवाई का दिन-प्रतिदिन का कारण होने के कारण, वे उपरोक्त निर्णय का लाभ लेने के हकदार हैं, भले ही देर से ही सही।

9. साथ ही, यह न्यायालय उनके द्वारा की गई अत्यधिक देरी से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है और इसलिए, इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अनुचित वित्तीय लाभ को देना, अपनी गलती पर प्रीमियम देना होगा। जैसा कि कहा गया है, जबकि 24 वर्षों की देरी पर्याप्त है, न्यायालय बकाया राशि के पुरस्कार को वर्तमान याचिका दायर करने से पहले के तीन वर्षों तक सीमित करना उचित समझता है। शेष अवधि के लिए, यदि लागू हो तो काल्पनिक लाभों को छोड़कर, वे किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। ऐसा आदेश दिया गया है।

10. तदनुसार, रिट याचिकाओं को सीमित सीमा तक अनुमति दी जाती है कि उत्तरदाता रिट याचिका दायर करने की तारीख से नियमितीकरण का लाभ देने के लिए आवश्यक अभ्यास करेंगे, जिसे निर्णय और आदेश दिनांक 07.10.1993 द्वारा अनुमति दी गई थी

और तदनुसार काल्पनिक लाभों की गणना की गई थी, लेकिन वित्तीय लाभ तत्काल आदेश के पूर्ववर्ती पैरा-9 के अनुसार वितरित किए जाएंगे।

11. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ विभाग से संपर्क करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

12. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।